CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 29 ▫ अंक- 45 ▫ रायपुर, मंगलवार 10 मार्च 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

सदन में गूंजा नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने बताया– 5 सालों में किया 4.24 करोड़ का भुगतान

चूहों के धान खाने पर विपक्ष लाया स्थगन, अग्राह्य होने पर गर्भगृह में पहुंचे विपक्षी सदस्य

रायपुर, 10 मार्च (हाईवे चैनल)। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगज़ीन को प्रदेश में बीते सालों में दिए गए विज्ञापनों की जानकारी मांगी गई. मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को पांच सालों में 4.24 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया. वहीं नवसृजन को इस अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया.

सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि 2019–20 से 2025–26 तक जनसंपर्क विभाग ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगज़ीन को विज्ञापन मद में कितनी राशि दी है, इनका कार्यालय कहां है और यह कहां से संचालित से होते हैं? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को वर्ष 2019–20 को 34 लाख, 2020–21 में 58 लाख, 2021–22 में 68 लाख, 2022–23 में 1.28 करोड़ और 2023–24 में 1.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया. 2024–26 में कोई राशि नहीं दी गई है. इस दौरान नवसृजन मैगज़ीन को कोई भुगतान नहीं किया गया, संडे नवजीवन को 3 करोड़ 6 लाख का विज्ञापन मिला है. उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड के प्रबंधकर्ता पवन बंसल है, और इसके मुखिया कौन है पूरा देश जानता है. पूरक प्रश्न में पूछा कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के विचारों के मुख पत्र को पैसा दे सकती है क्या? क्या जिन्होंने दिया है उनपर कार्यवाही होगी? भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि विज्ञापन किस नीति के तहत् ये दिया गया, क्या इसकी जाँच होगी क्या? इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 8 लाख प्रति पृष्ठ के आधार पर दिया गया. विज्ञापन नियमावली 2019 के आधार पर विज्ञापन दिए गए.

इधर सदन में आज विपक्ष चूहों द्वारा धान खाने के मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर आया. आसंदी के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने पर नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की. इसके साथ गर्भगृह में पहुंचने पर स्वमेव निलंबित हुए.सदन की कार्यवाही के दौरान नेता–प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने धान खरीदी समितियों में चूहों के धान खाने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के चलते 4600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार धान का सुरक्षा कर पाने में नाकाम रही है. सरकार गलत नीति से बड़ा नुकसान हुआ.

आसंदी के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने पर सदन में जमकर नारेबाजी करते हुए गर्भ गृह में पहुंचे विपक्षी सदस्य स्वमेंव निलंबित हुए. इसके बाद सदन परिसर में कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए मुसवा के नाम पर सरकार से भ्रष्टाचार बंद करने की बात कहते हुए जमकार नारेबाजी भी की.

सरकार इतनी कमजोर कि नहीं हटा पा रही है अतिक्रमण

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र

शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा

इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही के दौरान डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण स्थान पर अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकार इतनी कमजोर है कि आबंटित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है. जवाब में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कलेक्टर से अतिक्रमण हटाने पर चर्चा होने की जानकारी दी.

कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने सवाल किया कि उस जमीन पर किसका कब्जा है? उस जगह पर शाखा भवन निर्माण का भूमिपूजन हो चुका है, लेकिन निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बैंक की शाखा किराए पर चला रही है. शाखा निर्माण की राशि स्वीकृत है, इसके बाद भी भवन निर्माण क्यों नहीं हुआ? मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भवन नहीं है, इसलिए किराए से चला रहे है. इस पर हर्षिता बघेल ने कहा, बैंक किसानों के लिए है. किसानों को सुविधा नहीं मिल रही है. कब तक अतिक्रमण हटेगा? कब तक भवन बनेगा? मंत्री केदार कश्यप ने कहा, जल्द से जल्द बनाएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न में कहा, कितनी जमीन आबंटित है? कितनी जमीन है? कितनी जमीन पार्किंग के लिए है? मंत्री केदार कश्यप ने कहा, 2200 वर्ग जमीन आबंटित है. 3 हजार वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पार्किंग के लिए जरूरत है. इस पर भूपेश बघेल ने कहा, आपके पास 19 हजार वर्ग फ़ीट जमीन खाली है. इसका मतलब आप निजी व्यक्ति को फायदा पहुचाने के लिए अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहे हैं. इस पर मंत्री ने दोहराया कि जल्द से जल्द अतिक्रम हटाएंगे.

विधायक ओंकार साहू के सवाल पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धमतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओंकार साहू ने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में संभावित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों को जारी किए जा रहे फिटनेस प्रमाण–पत्रों तथा परिवहन नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर विस्तृत जानकारी मांगी। विधायक ओंकार साहू ने सदन में पूछा कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं तथा इसका जिला–वार विवरण क्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि उक्त अवधि में परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन और बिना बीमा के संचालन करने वाले वाहनों के खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज किए गए तथा उनसे कितनी राशि की वसूली की गई।इस प्रश्न के जवाब में प्रदेश के परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी किए जाने की कोई जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के कुल 77,810 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनसे लगभग 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये की वसूली की गई है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप के इस जवाब पर विधायक ओंकार साहू ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार यह शिकायतें सामने आती रही हैं कि कई स्थानों पर बिना उचित भौतिक परीक्षण के भी वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है तो यह भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।विधायक साहू ने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी दिखाई दे रही है। सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी यदि सरकार और संबंधित मंत्री के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है तो यह अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इससे यह भी आशंका पैदा होती है कि परिवहन विभाग में कहीं न कहीं लापरवाही या अनियमितता हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है।उन्होंने भाजपा सरकार और परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक ओंकार साहू ने कहा कि सड़क सुरक्षा और आम नागरिकों की जान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए।

एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर केंद्र सख्त जमाखोरी रोकने के लिए एस्मा लागू

नई दिल्ली, 10 मार्च (न्यूज चैनल)। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी रोकने और घरेलू गैस संकट को टालने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईएसएमए) लागू किया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और काले बाजारी गतिविधियों पर रोक लगाना है। सूत्रों के अनुसार, ईएसएमए लागू होने के बाद प्राथमिक सेक्टर्स को एलपीजी और अन्य ईंधन की सप्लाई में विशेष प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि अस्पताल, स्कूल, सरकारी संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई थी। ऐसे में ईएसएमए का लागू होना संकट से निपटने और आम जनता को राहत देने का बड़ा कदम है।आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एक कानून है, जिसे जीवन–निर्वाह से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रभावित होने से रोकने के उपाय किए जाते हैं, ताकि आम जनता पर असर न पड़े।

पाकिस्तान में फटा पेट्रोल बम, स्कूल–कॉलेज बंद, शहबाज–मुनीर की सांसे अटकी

नई दिल्ली, 10 मार्च (न्यूज चैनल)। ईरान के साथ जारी अमेरिका इजराइल युद्ध ने रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में पसरे तनाव का असर पेट्रोल सप्लाई पर पड़ा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की भयानक किल्लत हो गई है। कहा जा सकता है कि पेट्रोल बम फटा है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ?55 का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कई तरह के खर्चों की कटौती योजना का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए ऐलान किया कि सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ चार दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत से स्कूल दो हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। हफ्ते में सिर्फ चार दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है।

मगर इसका असर बैंकों पर नहीं होगा। तमाम स्कूलों को रवा हफ्ते के आखिर से दो हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50त्न कम ईंधन मिलेगा। सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तमाम स्कूल दो हफ्ते तक बंद रहेंगे और सभी उच्च शिक्षा संस्थान ऑनलाइन कक्षाएं तत्काल शुरू करेंगे। पाकिस्तान में आलम यह है कि कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर इतने ही पेट्रोल बचे थे कि वे सिर्फ एक से डेढ़ घंटे ही चल पाते। दो–ती दिन से पेट्रोल नहीं आए। शॉर्टेज हुई है हमारे तकरीबन आधा पंप यानी कि बंद हो चुका है पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया और हमारे पास जितना कुछ स्टॉक पड़ा है यह तकरीबन कोई डेढ़ डेढ़ दो घंटा और चल सकता है और पीछे से कोई कंफर्म नहीं है कि अभी तक कोई सप्लाई आनी है कि नहीं आनी है।

ब्रेकिंग न्यूज

मिट्टी धंसने से दीवार गिरी, 7 मजदूरों की मौत, कई दबे होने की आशंका

नई दिल्ली, 10 मार्च (न्यूज चैनल)। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में निर्माणाधीन दीवार के ढह जाने से सात मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना सोमवार शाम गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में हुई। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात करीब आठ बजे दीवार ढहने से 12 से 15 मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

चूहा- सुनती हो, प्रदेश में भी अब अफीम की खेती शुरू हो गई है।

चुहिया- हां जी, इसे ही तो फसल चक्र परिवर्तन कहते हैं।

लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम ने विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र

समर्थकों ने किया स्वागत

रायपुर, 10 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। सोमवार को दोनों नेत्री प्रमाण पत्र लेने विधानसभा पहुंचीं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दोनों सांसदों ने एक–दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की और गले मिलकर बधाई दी। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं दीं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में नामांकन वापसी के बाद दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गईं। इसके बाद आज उन्होंने विधानसभा पहुंचकर आधिकारिक तौर पर अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दोनों सांसदों ने इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे राज्य और जनता के हितों को राज्यसभा में मजबूती से उठाने का काम करेंगी।

पहली बार दोनों पार्टी से महिला उम्मीदवार

ऐसा पहला संयोग बना है जब राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार दोनों पार्टियों ने महिला को उम्मीदवार बनाया। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें आती हैं। फिलहाल पांच से अब तीन सांसद महिला होंगी। हालांकि कांग्रेस की रंजीता रंजन का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक पांच में से चार सांसद कांग्रेस के थे, लेकिन अब बीजेपी की संख्या बढ़ेगी। बीजेपी के सदन में दो सदस्य हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के तीन सदस्य रहेंगे। दोनों ही पार्टियों ने इस बार जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी बनाए हैं।

विधानसभा चुनाव में पार्टी ने दोनों को नहीं दिया था मौका

छत्तीसगढ़ में अनोखा समीकरण बना है कि दोनों ही महिला नेता जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है वह 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने दोनों को मौका नहीं दिया था। अब राज्यसभा के लिए भेजकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। फूलोदेवी नेताम बस्तर से आती हैं और कांग्रेस का बड़ा महिला चेहरा मानी जाती हैं। वह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए भेजी जा रही हैं। वह छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा पार्टी में लंबे समय से प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। वह रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं, जबकि अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा है।

अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, झाड़ियों में छिपा 6000 किलो लाहन बरामद

बिलासपुर, 10 मार्च (हाईवे चैनल)। जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के सख्त निर्देश पर बिलासपुर पुलिस द्वारा निरंतर 'प्रहार' जारी है, जिसके तहत कोनी क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के नेतृत्व में कोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें की जैसे ही कोनी पुलिस को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि घुटकु–स्टेशन पारा से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ऊँची घास और घने झाड़ों के बीच अवैध महुआ शराब बनाने की सोच रखते हुए भारी मात्रा में कच्चा माल छिपाकर रखा गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने आबकारी विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से बताए गए स्थान पर दबिश दी, जहाँ तलाशी के दौरान लंबी घास के बीच छिपाकर रखे गए 300 नग प्लास्टिक के डिब्बे बरामद किए गए, जिनमें कुल 6000 किलोग्राम महुआ लाहन भरा हुआ था। हालांकि, होने वाली कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस की टीम सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बरामद किए गए भारी मात्रा में लाहन को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया है।

सीआईडीसी की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट सख्त, अनुकंपा नियुक्ति मामले में सही जानकारी नहीं देने पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

बिलासपुर,10 मार्च (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सीआईडीसी की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सही जानकारी पेश नहीं करने और कैजुअल अप्रोच अपनाने के कारण सीआईडीसी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना (कॉस्ट) लगाया है। यह राशि तीन सप्ताह के भीतर देनी होगी। जांजगीर निवासी अमित कुमार राठौर ने हाई कोर्ट में अपील की थी, इसमें बताया कि उसके पिता सीआईडीसी में पदस्थ थे और 2020 में सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था। अमित ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 2021 में आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय तक कोई निर्णय न होने पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। पूर्व में सिंगल बेंच ने सीआईडीसी को 90 दिनों के भीतर दावे पर विचार करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, बाद में सीआईडीसी ने एक रिव्यू पिटीशन पेश कर दावा किया कि आवेदक की मांग पहले ही खारिज की जा चुकी है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया था। डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई के दौरान पाया कि जब मूल याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तब सीआईडीसी ने कोर्ट को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी। इस पर सीआईडीसी की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें एडवांस कॉपी पर पेश होना पड़ा था, इसलिए जानकारी नहीं थी।

जगदलपुर से स्पेशल ट्रेन चला रहा रेलवे

जगदलपुर,10 मार्च (हाईवे चैनल)। बस्तर क्षेत्र के यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जगदलपुर से ठाकुर नगर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह स्पेशल ट्रेन एक ट्रिप के लिए चलाई जाएगी, जिससे बस्तर क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। ट्रेन नंबर 08563 जगदलपुर–ठाकुर नगर स्पेशल ट्रेन 15 मार्च 2026 को सुबह 08ः00 बजे जगदलपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन 08.55 बजे जेयपुर पहुंचेगी और 09.00 बजे रवाना होगी। इसके बाद 10.00 बजे कोरापुट पहुंचेगी और 10.25 बजे प्रस्थान करेगी। दोपहर 13.45 बजे रायगढ़ा पहुंचेगी और 14.10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 16 मार्च को सुबह 10.45 बजे ठाकुर नगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 08564 ठाकुर नगर–जगदलपुर स्पेशल ट्रेन 18 मार्च 2026 को शाम 06.00 बजे ठाकुर नगर से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 19 मार्च को 14.40 बजे रायगढ़ा पहुंचेगी और 15.05 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद 19.25 बजे कोरापुट पहुंचेगी और 19ः50 बजे रवाना होगी। 20.55 बजे जयपुर पहुंचेगी और 21.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन रात 22.45 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन रास्ते में जयपुर, कोरापुट, रायगढ़ा, सिंगापुर रोड, मुनिगुड़ा, केसिंगा, टिटलागढ़, बलांगीर, बरगढ़ रोड, संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, आसनबोनी, खड़गपुर, अंडुल और भटनगर स्टेशनों पर रुकेगी। इतने कोच होंगे ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 3 थर्ड एसी, 6 स्लीपर, 5 जनरल कोच और 2 सेकेंड क्लास लगेज सह दिव्यांगजन कोच लगाए गए हैं।

CMYK